



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 21 सितम्बर, 2023

भाद्रपद 30, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 1143/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0 232-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (291)-2023

लखनऊ, 21 सितम्बर, 2023

अधिसूचना

प0आ0-475

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से मालों की पूर्ति करने वाले व्यक्तियों को जिससे उक्त अधिनियम की धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण किया जाना अपेक्षित हो, एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती हैं और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त, कुल आवर्त की धनराशि से अधिक नहीं हो, जिसके ऊपर एक पूर्तिकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी है, उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्तियों की श्रेणी के रूप में, निम्नलिखित शर्तों के अधधीन होंगे, अर्थात् :-

- ऐसे व्यक्ति माल की कोई अन्तर्राज्यीय पूर्ति नहीं करेंगे ;
- ऐसे व्यक्ति एक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से अधिक में इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से मालों की पूर्ति नहीं करेंगे ;
- ऐसे व्यक्तियों से आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 43 सन् 1961) के अधीन जारी स्थायी खाता संख्यां रखने की अपेक्षा की जायेगी ;

(iv) ऐसे व्यक्ति, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से किसी माल की पूर्ति करने से पूर्व, आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 43 सन् 1961) के अधीन जारी अपना स्थायी खाता संख्या, अपने कारबार के स्थान का पता और राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, जिनमें ऐसी पूर्ति करने का इच्छुक हो सामान्य पोर्टल पर घोषित करेंगे, जो सामान्य पोर्टल पर विधिमाम्यकरण के अधधीन होगा ;

(v) ऐसे व्यक्तियों को, खंड (iv) के अनुसार घोषित स्थायी खाता संख्या के सफलतापूर्वक विधिमाम्यकरण के लिए सामान्य पोर्टल पर एक नामांकन संख्या प्रदान की गई है ;

(vi) ऐसे व्यक्ति को एक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में एक से अधिक नामांकन संख्या प्रदान नहीं की जाएगी ;

(vii) ऐसे व्यक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से किसी माल की पूर्ति नहीं की जाएगी, जब तक कि ऐसे व्यक्तियों को सामान्य पोर्टल पर नामांकन संख्या प्रदान नहीं की गई हो ; और

(viii) जहां ऐसे व्यक्तियों को उक्त अधिनियम की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की पश्चात्पूर्ति अनुमति दी जाती है, नामांकन संख्या रजिस्ट्रीकरण के प्रभावी दिनांक से विधिमाम्य नहीं रह जाएगी।

2—यह अधिसूचना दिनांक 1 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1143 / XI-2-23-9(47)-17-T.C.232-U.P.Act-1-2017-Order (291)-2023, dated September 21, 2023 :

No. 1143 / XI-2-23-9(47)-17-T.C.232-U.P.Act-1-2017-Order (291)-2023

Dated Lucknow, September 21, 2023

IN exercise of the powers under sub-section (2) of section 23 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017)(hereinafter referred to as the "said Act"), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby specifies the persons making supplies of goods through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52 of the said Act and having an aggregate turnover in the preceding financial year and in the current financial year not exceeding the amount of aggregate turnover above which a supplier is liable to be registered in the State or Union territory in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 22 of the said Act, as the category of persons exempted from obtaining registration under the said Act, subject to the following conditions, namely: —

(i) such persons shall not make any inter-State supply of goods;

(ii) such persons shall not make supply of goods through electronic commerce operator in more than one State or Union territory;

(iii) such persons shall be required to have a Permanent Account Number issued under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961);

(iv) such persons shall, before making any supply of goods through electronic commerce operator, declare on the common portal their Permanent Account Number issued under the

Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), address of their place of business and the State or Union territory in which such persons seek to make such supply, which shall be subjected to validation on the common portal;

(v) such persons have been granted an enrolment number on the common portal on successful validation of the Permanent Account Number declared as per clause (iv);

(vi) such persons shall not be granted more than one enrolment number in a State or Union territory;

(vii) no supply of goods shall be made by such persons through electronic commerce operator unless such persons have been granted an enrolment number on the common portal; and

(viii) where such persons are subsequently granted registration under section 25 of the said Act, the enrolment number shall cease to be valid from the effective date of registration.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2023.

By order,
NITIN RAMESH GOKARN,
Apar Mukhya Sachiv.